MR. CHAIRMAN: You write a letter. I will consider.

Demolition of Jhuggis in Delhi

*145. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of jhuggis and dhabas demolished in Delhi and New Delhi during the current year; and

(b) what is the number of jhuggi dwellers and dhaba owners provided with alternative accommodation and sites?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) According to information received from DDA, MCD, NDMC, Delhi Cantonment Board, Ministry of Defence, & Department of Railways 8088 jhuggis and 64 Dhabas have been demolished in Delhi and New Delhi during the current year. In addition DDA removed 840 other encroachments from its land but has not kept any separate figure of dhabas removed.

(b) Alternative accommodation has been provided by the DDA as follows:—

(1) Allotment of accommodation to Jhuggi Jhompri dwellers in transit camps—4185 Units.

(2) Allotment of commercial sites—63.

DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: My first Supplementary is this. Why did the DDA not keep the figures of demolished Dhabas? Will the Minister instruct the DDA to keep figures of Dhabas demolished in future?

श्री दलबीर सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने करन्ट ईयर में पिछले चार महीनों में जो डी०डी०ए० ने 6815 अवैध अतिक्रमण हटाये हैं उनके बारे में पूछा है । इनमें से 5875 झुग्गी-झोंपड़ी निवासी हैं और शेष जो 840 हैं वे फुटकर अतिक्रमण हैं, जैसे किसी ने चारदीवारी बना ली या खोखा बना लिया या डेरी बना ली । इस तरह के अतिक्रमण हैं । इन 5875 मामलों में 4185 परिवारों को डी०डी०ए० ने अपने ट्रांजिट कैम्पस के माध्यम से आलटरनेटिव आवास दे दिया है और जो बाकी रह गये हैं उनके पास वैध कागजात न होने की वजह से उनको ये सुविधाएं नहीं दी गई हैं ।

DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: My first question has not been answered. The Minister had stated that the DDA removed 840 other encroachments from its land, but has not kept any separate figures of Dhabas removed. So, my question is why did the DDA not keep figures for the demolished Dhabas? This thing has not been answered.

My second Supplementary question is this. How long will Jhuggi dwellers be accommodated in transit camps and by what time will they provide them with alternative accommodation?

श्री दलबीर सिंह : श्रीमन्, इनमें से बहुत कम रह गये हैं । हम यह प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे पास ट्रांजिट कैम्पस होंगे, हम उनको देंगे । लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि बाकी जो लोग बचे हैं, वे जो झुग्गी-झोंपड़ी वाले हैं उनके पास वैध कागज-पत्र नहीं थे, कोई वैध डाकुमैन्ट्स नहीं हैं । इस वजह से उनको बसाने में दिक्कत आ रही है ।

SHRI BHAGATRAM MANHAR: While I welcome the Government's action in removing unauthorised constructions, we have to look at the problem from the humanitarian angle also. That is why I would like to know from the hon. Minister whether his Ministry wishes to assure the

House that alternative accommodation will first be provided to the people before evicting them.

श्री दलबीर सिंह : महोदय, शासन का इस प्रकार के मामलों में हमेशा मानवीय दृष्टिकोण रहा है । जहां तक इन झुग्गी-झोंपड़ी वालों का संबंध है, दिल्ली और हर बड़े-बड़े मैट्रोपोलिटन शहरों में लोग आते हैं और अवैध कालोनियां बन जाती हैं । इस संबंध में पिछली बार होम मिनिस्ट्री में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारे पदाधिकारी बुलाये गये थे । बराबर हम इस पर विचार करते हैं । जैसे ही हमारे पास ट्रांजिट कैम्पस होंगे, हम उनको देंगे ।

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Sir, may I know from the Minister whether he has any figures of the total number of jhuggis and dhabas in Delhi? Are there any health problems in these jhuggis? Whether drinking water is available to them while they are in the jhuggis?

श्री दलबीर सिंह : मान्यवर, यह सवाल जो है यह इससे रिलेटिड नहीं है, इसलिये अभी यह बताना संभव नहीं होगा ।

SHRI KAPIL VERMA: The figures given in the reply of the Minister shows that only half of the jhuggi dwellers and dhaba dwellers have been accommodated in the camps. But I would like to know what arrangements have been made for the rest of the jhuggi and dhaba dwellers?

SHRI DALBIR SINGH: What, Sir?

MR. CHAIRMAN: He says accommodation has been provided only for the half 8,088 jhuggis. What about the rest?

SHRI KAPIL VERMA: Sir, out of 8,088 jhuggis which have been demolished in Delhi and New Delhi only 4,185 have been accommodated. But what about rest of the dwellers?

श्री दलबीर सिंह : मैंने पहले ही अपने उत्तर में कहा है जहां तक इनको बसाने का सवाल है क्योंकि जब सर्वे किया गया तो इनके पास ऐसे कोई डाकुमेन्ट नहीं मिले, इस वजह से इस संबंध में हमको दिक्कत आ रही है ।

श्री जो० स्वामी नायक : चेयरमैन साहब, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वे जानते हैं कि जलेबी चौक की 50 झुग्गियों को हटाकर उनको सुलतानपुरी में बसाया गया था और 1983 में, 16 सितम्बर को श्री जगमोहन, लैफ्टिनेन्ट गवर्नर दिल्ली के कर कमलों द्वारा उनके लिये मकान बनाने की फाउन्डेशन रखी गई थी लेकिन आज तक कोई काम उन झुग्गियों के लिये नहीं हुआ । क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि आज तक वहां काम नहीं किया गया? महोदय, अभी यह मालूम हुआ है कि उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है । तो क्या मंत्री जी वह बताने की कृपा करेंगे कि इन झुग्गियों जिनमें बंजारे, सिरकी बनाने वाले रहते हैं क्या उनको वहां से न हटाने का कोई आदेश देंगे?

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने जो कहा है वह सीधा इस सवाल से संबंधित नहीं है । लेकिन फिर भी यह बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने 1960 में दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी उन्मूलन योजना प्रारम्भ की थी और 1977 तक यह चली । इसके बारे में जो आंकड़े बतलाये गये हैं उसके अनुसार इस योजना के अन्तर्गत झुग्गी निवासियों के लिये पुनर्वास कालोनियों के लिये 80 वर्ग गज जमीन 3867 लोगों को और टैनामेंट 3560 लोगों को दिये गये तथा 25 वर्ग गज के जो प्लाट दिये गये वे 1 लाख 96 हजार हैं । इसलिये यह जो पिछली योजना है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है उसके आंकड़े हैं ।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: The real problem arises because these unauthorised constructions are allowed to

come up. They are constructed and continued very often with the connivance of the authorities. What is necessary is timely detection and removal. Otherwise this evil menace will keep on growing. If you remove a jhuggi or a dhaba within a period of month's of its coming into existence, we also would not have any claim to have an alternative accommodation. But it does look that all these jhuggis and dhabas have been there for a considerable length of time. So the question which I want to ask is (a) how many of jhuggis and dhabas were there before they have been demolished?; and (b) have you set up any machinery by which unauthorised constructions shall be removed within a period of two months of their being put up?

श्री दलबीर सिंह : सर, माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसके बारे में चार महीने के हमारे पास आंकड़े हैं। फिर भी आपने जो कहा है उस सजेशन को हम मान रहे हैं। इस संबंध में होम मिनिस्ट्री ने 1965 में एक मीटिंग की थी और इसमें माननीय सदस्यों ने भी राय जाहिर की थी। इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, आफिसेज हैं उनकी जमीनें भी खाली हैं और उनको भी कहा गया है, रेक्वेस्ट की गई है कि वे यह देखें ताकि कोई इनक्रोचमेंट न हो, वे किसी को न घुसने दें। आपका सजेशन मान लिया गया है और आने वाले समय में डी० डी० ए० ने फील्ड आफिसर रखे हैं जो इस पर रोक लगा रहे हैं।

श्रीमती शान्ती पहाड़िया : श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जो संगम बिहार बस्ती है वह बहुत बड़ी बस्ती बन गई है। मैं जानना चाहती हूं कि उसको हटाया जायेगा या उसको बसाया जायेगा। वैसे उन्होंने वह जमीन किसानों से लेकर खरीदी है उस पर बहुत अच्छे अच्छे मकान बना लिए हैं। काफी बड़े बड़े प्लाट खरीदे हैं। उस पर मंत्री जी का क्या विचार है?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

European Economic Community Aid for "Operation Flood" Project

*146. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to seek further assistance and support from the European Economic Community to the "Operation Flood Project" which ended in April, 1985;

(b) what is the quantum of assistance in cash and kind so far received from the European Economic Community; and

(c) what have been the achievements of operation flood Project so far and whether the targets set out have been achieved?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BUTA SINGH): (a) There is a proposal to seek assistance from European Economic Community for continuation of Operation Flood project during the Seventh Five Year Plan.

(b) The Indian Dairy Corporation has received 2,16,583.827 MT of skim milk powder, 62,401.540 MT of butter oil, 16,577.050 MT of butter and 497.120 MT of refined rapeseed oil upto March, 1985.

(c) Table below indicates targets and achievements of selected components under Operation Flood II during the Sixth Five Year Plan period i.e. 1980-81 to 1984-85.